पदों की संख्या, उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या और आधारिक संरचना संबंधी सुविधायें शामिल हैं।

(ङ) और (च) इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पालन करते हैं।

Pakistan's intention to raise Kashmir Issue in next Session of the UN General Assembly

3573. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Pakistan is active again in soliciting the help of Muslim countries in getting a resolution moved in the United Nations General Assembly's 50h Session next year; and

(b) if so, the steps taken by Government to thwart the ugly designs of Pakistan on Jammu and Kashmir?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Pakistan has been continuously trying in different UN forums to get a resolution adopted against India on Jammu and Kashmir issue. The Government of India have kept all member States of the United Nations, as well as the members of the Organisation of Islamic Conference (OIC), informed of our perspective on Jammu and Kashmir through our Missions abroad as well as by briefing the Missions of those countries in New Delhi, on a continuous basis.

Nuclear weapons developed by Pakistan

3574. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem published in certain news papers about reported statement of Pakistani Opposition Leader, Mr. Nawaz Sharif to the effect that Pakistan had an atom bomb:

(b) whether it is a fact that former Chief of Pakistani armed forces, General Aslam Beg, has also stated that Pakistan not only had the capbility of developing nuclear weapons, but had already developed one; and

(c) if so, the details of such weapons available with Pakistan and what is the reaction of the Government of India in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) Government have noted a statement of the former Prime Minister of Pakistan in August 1994 to the effect that Pakistan possessed an atomic bomb.

(b) Gen. (Retd.) Aslam Beg former chief of Pakistani Armed Forces has reportedly made statements to the press that Pakistan has acquired Complete nuclear capability.

(c) Government are aware that Pakistan has a clandestine Weapon-oriented nuclear programme. This programme has been and is sustained through acquisition of materials and technology from foreign sources.

Government constantly monitor all developments having a bearing on India's security and take necessary measures to safeguard it.

भारत-नेपाल संबंधों के बारे में नेपाल का अधिकारिक संदेश

3575. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत सरकार को अभी तक कोई आधिकारिक सन्देश मिला है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि नेपाल के प्रधान मंत्री भारत-नेपाल सम्बन्धों के सम्पूर्ण आयामी पर विचार करना चाहते हैं जबकि उप प्रधान मंत्री भारत-नेपाल को 1950 की सन्धि के बारे में मौन है। जिसके परिणामस्वरूप टनकपुर बांध परियोजना के रुकने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत-नेपाल सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिए और 1950 की सन्धि को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) नेपाल की नई सरकार ने भारत के साथ संबंध सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। नेपाल के उप प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल ने 6 से 10 फरवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के बाद नेपाल के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन अधिकारी 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत आए। नेपाल के उप प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री की इन यात्राओं के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें 1950 की भारत-नेपाल संधि सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलू शामिल थे। भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध संवर्धित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। नेपाल के प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी किया गया संयुक्त वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)।

टनकपुर बांध परियोजना, जो एक पनबिजली परियोजना है, जुलाई, 1992 में शुरू की गई थी। यह परियोजना सामान्य रूप से कार्य कर रही है और इसमें किसी समस्या की आशंका नहीं है।

विवरण

नेपाल के प्रधान मंत्री की 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत यात्रा संयुक्त वक्तव्य

भारत के प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधान मंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह अधिकारी 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत की सरकारी सद्भावना यात्रा पर आए हुए हैं। नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ श्रीमती साधना देवी अधिकारी, श्री चन्द्र प्रकाश मैनाली, स्थानीय विकास एवं सप्लाई मंत्री, श्री भीम बहादुर रावल, वाणिज्य, पर्यटन एवं नागर विमानन राज्य मंत्री, श्री हरि प्रसाद पांडेय, उद्योग एवं जल संसाधन राज्य मंत्री और श्री मंगल सिद्धी मानन्धर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग भारत आए।

2. नेपाल के प्रधान मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति से भेंट की और वे राजघाट गए जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के साथ बैठकें कीं। दोनों प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली प्रतिनिधिमंडलों ने भी आपसी हित के मसलों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बैठक की।

3. निष्ठा, मित्रता और सद्भाव जो भारत और नेपाल के बीच निकट संबंधों की विशेषता है और एक-दूसरे की सम्पूर्ण सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखंडता तथा स्वाधीनता के प्रति परस्पर सम्मान इन विचार-विमर्शों की विशेषता थी। व्यापक विचार-विमर्शों के दौरान द्विपक्षीय मसलों, भारत-नेपाल संबंधों के और अधिक विकास, भारतीय उप-महाद्वीप की स्थिति और आपसी हित के अन्य प्रश्नों पर चर्चा हुई।

4. दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों के संवर्धन के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरायी और एक ऐसे भविष्य की आशा की जहां ये संबंध सहयोगात्मक प्रयासों के नए क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ किये जाएंगे। दोनों प्रधान मंत्री इस बात से प्रोत्साहित हुए कि भारत और नेपाल के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके बीच विचार-विमर्श में 1950 की शान्ति एवं मैत्री संधि की समीक्षा सहित द्विपक्षीय

संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई । वे इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों देशों के उपयुक्त स्तर पर इस पर तथा द्विपक्षीय हित के सभी संगत मसलों पर विचार-विमर्श जारी रखेंगे ।

5. दोनों सरकारों ने संप्रभुता, समानता, प्रादेशिक, अखंडता, राष्ट्रीय स्वाधीनता बल का प्रयोग न करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलो में अहस्तक्षेप और सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई । भारत और नेपाल दोनों एक-दूसरे की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझते हैं कोई भी पक्ष अपने प्रदेश में किसी भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा जो दूसरे की सुरक्षा के प्रतिकूल हो ।

व्यापार और पारगमन

6. दोनों प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की । दोनों सरकारों द्वारा 1992 से किये गये तरजी ही प्रबंधों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में हाल में हुए वृद्धि से वे प्रोत्साहित हुये ।

7. नेपाल के महामहिम की सरकार और भारत सरकार के बीच हुये विचार-विमर्शों के आधार पर इस बात पर सहमति हुई कि व्यापार और पारगमन प्रणाली में निम्नलिखित और सुधार किये जायेंगे:

(i) नेपाल के मार्गस्थ व्यापार को कांडला तथा बम्बई के अतिरिक्त पत्तनों की सुविधा मिलेगी और यह सुविधा उन्हीं शर्तों के आधार पर मिलेगी जो भारतीय राष्ट्रिकों को उपलब्ध है बशर्ते माल का पारगमन सबसे कम दूरी वाले नामित रेल मार्गों के रास्ते सीमाशुल्क मोहरबंद आधानों में हो ।

(ii) नेपाल के ऐसे मार्गस्थ व्यापार के लिये रक्सोल में सीमा शुल्क निकासी की अतिरिक्त व्यवस्था जो कांडला, बम्बई और कलकत्ता से आने जाने के लिये सीमा शुल्क मोहर के अन्तर्गत आधान बन्द हो ।

(iii) दोनों देश संयुक्त रूप से ऐसे नेपाली उत्पादों का पता लगाने का प्रयास करेंगे, भारतीय मंडियों में तरजीह आधार पर जिनके प्रवेश के मामले में और अधिक सुधारों पर विचार किया जा सकता हो ।

(iv) भारतीय मंडियों में तरजही आधार पर प्रवेश संबंधी कार्यविधियों का जहां तक संबंध है, भारत नेपाल अन्तर सरकारी व्यापार और वाणिज्य समिति द्वारा इनकी समीक्षा की जायेगी ।

आपूर्तियां

8. इस बात पर सहमति हुई कि भारत पेट्रोलियम, उत्पादों, नमक, चीनी, चावल इत्यादि जैसी वस्तुओं को नियमित आपूर्ति में नेपाल की सहायता करता रहेगा ।

जल संसाधन

9. दोनों प्रधानमंत्रियों ने जल-संसाधन के मसले पर भी विचार-विमर्श किया । इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष महाकाली नदी के उपयोग का विकास करने के लिये अपने प्रयास जारी रखेंगे । नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल को अतिरिक्त लाभ देने के संबंध में कई प्रस्ताव रखे । भारत के प्रधान मत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संबंधित पहलुओं का ध्यान रखते हुये इन प्रस्तावों की जांच की जायेगी । इसके लिये परामर्श करने में कुछ समय लगेगा । इसके बाद दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि वे और विचार-विमर्श करेंगे तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगे ।

भारतीय सहायता परियोजनाएं

10. दोनों पक्षो ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अक्तूबर, 1992 में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से नेपाल में शुरू की गई भारत-नेपाल सहयोग परियोजनाओं का क्रियान्वयन कारगर ढंग से किया जा रहा है । धरान में वी०पी० कोइराला चिकित्सा संस्थान में विद्यार्थियों के प्रथम बैच को प्रवेश दिया गया है और परियोजना का कार्य सुचारू रूप से जारी है । कई, अन्य परियोजनायें पूर्ण हो गई है अथवा पूर्ण होने वाली हैं। इनमें से वे परियोजनायें जो अक्तूबर 1992 में भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के बाद पूर्ण की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं: रांगेली में टेलीफोन एक्सचेंज, राजविराज में औद्योगिक एस्टेट, हितौदा में संग्रहालय भवन, लुम्बिनी संग्रहालय भवन, कोल्हापुर और महाकाली के बीच महेन्द्र राजमार्ग का पश्चिमी क्षेत्र, रक्सौल (सिसिया) पुल, जयनगर जनकपुर रेलवे को दो इंजनों और छह रेल के डिब्बों की आपूर्ति, काठमांडू नगर की सफाई उपकरणों की आपूर्ति । अन्य परियोजनाओं की तैयारी कार्य सहज रूप से चल रहा है ।

11. दोनों सरकारों ने 1995–96 के दौरान निम्नलिखित सहमत और नई परियोजनायें निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार शुरू करने का निर्णय लिया है ।

1. पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कोल्हापुर–महाकाली क्षेत्र पर 18 पुल ।

2. रक्सौल–सिसिया ब्राडगेज रेल संपर्क ।

3. वीर चिकित्सालय का संवर्धन ।

4. पूर्व-पश्चिम विद्युत चालित रेलवे के लिये संयुक्त सर्वेक्षण ।

5. जयनगर–विजालपुर नेरोगेज रेल संपर्क के लिये दो इंजनों और 12 रेल के डिब्बों तथा बैगनों की आपूर्ति ।

6. ग्रेटर जनकपुर विकास परियोजना

दोनों पक्ष प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं पर उपलब्ध संसाधन केन्द्रित करने के लिये भी सहमत हुए हैं ।

12. नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल की यात्रा करने का निमंत्रण दिया है । यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया गया है, यात्रा की तिथियां राजनयिक माध्यमों से तय की जायेंगी ।

अप्रैल, 12, 1995
नई दिल्ली ।

US refusal to supply arms to Pakistan

3576. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the U.S. has stopped sending military hardwares and spares to Pakistan, and as a result Pakistan has acquired replacements from other sources; and

(b) the implications of Mirage-2000, acquisition by Pakistan vis-a-vis Indian Air Force?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) In 1990, as a result of the Pressler Amendment, the US stopped supply of military equipment to Pakistan. Government are aware of Pakistan's continued effort to inquire sophisticated weapons and technology from various alternative sources.

(b) Pakistan is interested in acquiring Mirage 2000 aircrafts from France. However, according to available information, the transaction has not been finalised so far. Our concerns about any arms sales to Pakistan disproportionate to Pakistan's legitimate defence